<u>परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी)</u>

परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) भारत में 500 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश के साथ परियोजनाओं में समस्याओं और नियामक बाधाओं के त्वरित समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र है। इसे 2013 में कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार में एक विशेष प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे 2015 में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था। 14 फरवरी 2019 से पीएमजी को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ मिला दिया गया है। निर्गम समाधान सहित निवेश प्रक्रिया के सभी चरणों में निवेशकों के लिए वन-स्टॉप सुविधा स्थल बनाने के लिए यह स्थानांतरण सक्षम किया गया था।

पीएमजी सभी मध्यम और बड़े आकार की सार्वजनिक, निजी और "सार्वजनिक-निजी भागीदारी" (पीपीपी) परियोजनाओं के संबंध में अनसुलझे परियोजना समस्याओं को सूचीबद्ध करना चाहता है और अनुमोदन, क्षेत्रीय नीति के मुद्दों और त्वरित कमीशनिंग में बाधाओं को दूर करने के लिए तेजी से ट्रैकिंग करता है। डीपीआईआईटी को चुनौतियों का सामना करने वाली सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नोडल निकाय के रूप में अधिदेशित किया गया है जो पीएमजी के माध्यम से उनके समाधान की सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख क्षेत्रों की कई परियोजनाएं हैं जिनके लिए पीएमजी समस्याओं का समाधान करता है। परियोजनाएं बड़े पैमाने पर ढांचागत प्रकृति से हैं, हालांकि पीएमजी सभी क्षेत्रों की परियोजनाओं को स्वीकार करता है जब तक कि वे प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये परियोजनाएं आम तौर पर इस तरह के क्षेत्रों से होती हैं:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, नागरिक उड्डयन
- अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाह और नौवहन
- रसायन, उर्वरक और पेट्रोरसायन
- उर्जा
- कोयला और खान
- शहरी विकास
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- वस्त्र
- पर्यटन
- दूरसंचार और आईटी सेवाएं

पीएमजी द्वारा उठाए गए मुद्दे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हैं। जिनमें शामिल है:

- **केन्द्रीय मंत्रालय**
    - पर्यावरण वन और वन्यजीव मंजूरी
    - इको सेंसिटिव जोन क्लीयरेंस
    - पेड़ काटने की अनुमति
    - वन विभाग द्वारा कार्य करने की अनुमति प्रदान करना
    - निजी रेलवे साइडिंग निर्माण के लिए स्वीकृति
    - औद्योगिक लाइसेंस अनुमति
    - पाइपलाइनों/पारेषण लाइनों की सड़क क्रॉसिंग
    - आवाजाही की अनुमति
    - जनसुविधाओं का स्थानांतरण
    - कोई अन्य केंद्र सरकार की मंजूरी/अनुमोदन
- **राज्य सरकारें**
    - भूमि अधिग्रहण के मुद्दे जैसे सरकारी अधिसूचना जारी करना/मुआवजे का संवितरण, स्वामित्व का हस्तांतरण और भूमि का कब्जा सौंपना तथा संबंधित मुद्दे।
    - अतिक्रमण हटाना
    - राहत और पुनर्वास योजना का अनुमोदन और कार्यान्वयन
    - वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
    - बिजली और जल आपूर्ति कनेक्शन का अनुदान
    - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (सीओई) और संचालन के लिए सहमति (सीओई) की स्वीकृति/अनुमति जारी करना।
    - सरकारी भूमि का हस्तांतरण
    - कानून और व्यवस्था के मुद्दों के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों का समर्थन
    - रास्ते का अधिकार/उपयोग के अधिकार की अनुमति देना

कोई अन्य राज्य सरकार की मंजूरी/अनुमोदन

लिंक: pmg.dipp.gov.in